बेरोजगारी [UNEMPLOYMENT]

बेरोजगारी का अर्थ (MEANING)

जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम हो तथा वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहे ताकि वह अपनी आजीविका चला सके, परन्तु उसे कोई काम न मिले तो उस व्यक्ति को बेरोजगार तथा इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं।

अन्य शब्दों में, *बेरोजगारी दर तथा किसी व्यक्ति व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को, जो कार्य करने के इच्छुक रहता है, प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता।*

बेरोजगारी के प्रकार

(1) ऐच्छिक बेरोजगारी (Voluntary Unemployment)—

जब रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हुए भी लोग चालू मजदूरी दर पर कार्य नहीं करना चाहते और बेकार रहते हैं तो यह ऐच्छिक बेरोजगारी की स्थिति होती है।

- स्थायी सेवित कर्मचारी, सेठ, साहूकार, आदि सम्पन्न वर्ग के ऐसे लोग जो अपनी सम्पत्ति की आय पर निर्भर रहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी के उदाहरण हैं।
- इसी प्रकार निवृत्तिवेतन पर निर्भर रहने वाले 'निवृत्त' लोग भी ऐच्छिक बेरोजगार (बेकार) कहे जाएंगे, क्योंकि वे मजदूरी दर पर कोई उत्पादन सम्बन्धी कार्य नहीं करना चाहते।

(2) अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary Unemployment)—

जब लोग चालू मजदूरी दर पर काम करने को तैयार रहते हैं, परन्तु उन्हें काम नहीं मिलता।

किसी अर्थ में वास्तविक समस्या, बेरोजगारी इसी समस्या से छुटकारा पाना है।

(3) घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)—

घर्षणात्मक बेरोजगारी की स्थिति तब पाई जाती है जब श्रम के स्थान परिवर्तन के मध्य समायोजन की कमी होती है।

रोजगार खोजने में, इस तरह की बेरोजगारी श्रम की गतिशीलता, रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में श्रमिकों की अनभिज्ञता, मशीनों की टूट-फूट, कच्चे माल की कमी, विशिष्ट सेवाओं के लिए वांछित योग्यता का अभाव तथा औद्योगिक संघर्ष, आदि कारणों से उत्पन्न होती है।

(4) मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)—

मौसमी बेरोजगारी मांग में मौसमी उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होती है।

जैसे चीनी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को वर्ष भर काम नहीं मिलता। कृषि श्रमिकों को कटाई-बुवाई के दिनों में काम मिलता है, वर्ष के शेष दिनों में वे बेरोजगार रहते हैं।

(5) प्रौद्योगिक अथवा तकनीकी बेरोजगारी (Technological Unemployment)—

इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है।

आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में यंत्रीकरण है, जहां नव-प्रवर्तन के कारण नई मशीनें तथा तकनीकें अपनाई जाती हैं। *नवीन तकनीकों के प्रयोग से श्रमिकों का विस्थापन होता है, जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है।* अन्य शब्दों में, जब नई तकनीकें पुराने श्रम को प्रतिस्थापित कर देती हैं तो कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे तकनीकी बेरोजगारी उत्पन्न होती है।

(6) संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)—

अर्थव्यवस्था में जब कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, तब इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। यह तब होती है जब उद्योगों की संरचना बदलती है और श्रमिकों की कौशल आवश्यकताएं बदल जाती हैं, जिससे कुछ श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं।

(7) चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)—

चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक चक्रों के कारण उत्पन्न होती है। मंदी के समय उत्पादन घटता है, जिससे रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है।

भारत में बेरोजगारी का स्वरूप (NATURE OF UNEMPLOYMENT IN INDIA)

सामान्यतः देश की सारी श्रम शक्ति रोजगार में नहीं लगी होती। अधिकतर उनका कम या अधिक भाग बेरोजगार होता है। बेरोजगारी की यह मात्रा अल्पविकसित देशों में विकसित देशों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इन देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है और रोजगार के अवसर सीमित होते हैं।

भारत में बेरोजगारी के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं—

(1) संरचनात्मक बेरोजगारी—भारत में बेरोजगारी का प्रमुख स्वरूप यही है, क्योंकि यहाँ पूंजी की कमी और श्रम की अधिकता है।

(2) अल्प-रोजगार (Underemployment)—जब व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता और कम काम करता है, तो उसे अल्प-रोजगार कहते हैं।

(3) खुली बेरोजगारी—जब व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, पर उसे काम नहीं मिलता।

(4) मौसमी बेरोजगारी—यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ कार्य केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है।

(5) शिक्षित बेरोजगारी—जब शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता।

(6) छिपी बेरोजगारी (Disguised Unemployment)—

जब अधिक श्रमिक कार्य में लगे होते हैं, पर उनके हटने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

उदाहरण के लिए, खेत में 3 व्यक्तियों की आवश्यकता है, परन्तु घर के सभी 5 व्यक्ति उस कार्य में लगे हैं। फिर भी इससे उत्पादन में कोई अन्तर नहीं आता है तो इस प्रकार 2 व्यक्ति इस कार्य में अधिक हैं। यही **अदृश्य या छिपी बेरोजगारी** है।

प्रो. वारसिक (Worsick) के अनुसार, "छिपी बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें श्रम का उपयोग अपूर्ण रूप से हो रहा हो।"

छिपी बेरोजगारी में निम्न लक्षण पाये जाते हैं—

(1) विकासशील या अविकसित देशों में पायी जाती है—छिपी बेरोजगारी विकासशील या अल्प विकसित देशों में पायी जाती है क्योंकि इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की गति तेज होती है, जबकि उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ता।

(2) सीमांत उत्पादकता शून्य—जिन देशों में छिपी बेरोजगारी पायी जाती है, उन देशों में बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है।

(3) परिवार रोजगार से सम्बन्धित—छिपी हुई बेरोजगारी सामान्यतः परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित होती है।

(4) सूचना का अभाव—छिपी बेरोजगारी से सम्बन्धित सूचनाएं प्रायः नहीं मिल पाती हैं क्योंकि यह व्यक्तियों में समाहित हो जाती है।

(5) विकसित व अल्प-विकसित देशों में छिपी बेरोजगारी की प्रकृति में अन्तर—विकसित देशों में भी छिपी बेरोजगारी पायी जाती है परन्तु उसकी प्रकृति में अन्तर होता है। विकसित देशों में यह अल्पकालिक होती है, जबकि अल्प-विकसित देशों में यह दीर्घकालीन होती है।

भारत में बेरोजगारी का अनुमान (ESTIMATE OF UNEMPLOYMENT IN INDIA)

भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पायी जाती है, परन्तु आंकड़ों के अभाव में सही ढंग से इसकी मात्रा का माप नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में तो आंकड़ों का बहुत अभाव है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी को मापना बहुत ही कठिन काम है। शहरी बेरोजगारी के सम्बन्ध में भी आंकड़ों की पर्याप्तता नहीं है। ये आंकड़े रोजगार कार्यालयों द्वारा तैयार किये जाते हैं।

समग्र बेरोजगारी दर — 4.9%

पुरुष — 4.1% महिला — 7.7%

ग्रामीण बेरोजगारी दर — 4.7%

पुरुष — 4.2% महिला — 6.4%

शहरी बेरोजगारी दर — 5.5%

पुरुष — 3.9% महिला — 12.4%

सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य — सिक्किम
सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य — छत्तीसगढ़
सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य — केरल (10%)

बेरोजगारी के दुष्परिणाम

राष्ट्र के लिए बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर समस्या है। इस समय कुल पंजीकृत बेरोजगारों में 60 प्रतिशत बेरोजगार पढ़े-लिखे हैं तथा प्रत्येक सात बेरोजगारों में से एक ही है। इस समस्या के कुछ दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं—

(1) मानव शक्ति का व्यर्थ जाना—बेरोजगारी एक राष्ट्र के लिए गंभीर समस्या होती है। इसके कारण मानव-शक्ति का उचित उपयोग नहीं हो पाता है और यह शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। यदि इसका उचित रूप से काम में लिया जाये तो यह राष्ट्र के लिए समृद्धि एवं प्रगति का साधन बन सकती है।

(2) सामाजिक समस्याओं का जन्म—जिस देश में बेरोजगारी होती है उस देश में नयी-नयी सामाजिक समस्याएं जैसे चोरी, डकैती, बेईमानी, अनैतिकता, शराबखोरी, जुआखोरी, आदि पैदा हो जाती हैं जिससे सामाजिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। शान्ति एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिस पर सरकार को भारी व्यय करना पड़ता है।

(3) राजनीतिक अस्थिरता—बेरोजगारी की समस्या देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर देती है, क्योंकि व्यक्ति हर समय राजनीतिक उठापटक में उलझे रहते हैं।

(4) आर्थिक सम्पन्नता में कमी—बेरोजगारी से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है जिससे जीवन-स्तर गिरता है। लोगों की क्रयशक्ति में गिरावट एवं निर्धनता में वृद्धि आर्थिक समस्या उत्पन्न करती है।

(5) अन्य दुष्परिणाम—बेरोजगारी के अन्य दुष्परिणाम हैं, जैसे औद्योगिक संघर्षों में वृद्धि, मालिकों द्वारा बेरोजगारों का लाभ उठाकर कम मजदूरी देना, फलतः पारिश्रमिक कम मिलना, कुपोषण, स्वास्थ्य समस्याएं आदि।

बेरोजगारी से सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक वातावरण दूषित हो जाता है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री **विलियम बेवरिज (William Beveridge)** ने लिखा कि *"बेरोजगार रखने के स्थान पर कांग्रेस को गड्ढे खुदवाकर वापस भरने के लिए नियुक्त करना ज्यादा उचित है।"*

बेरोजगारी के कारण (CAUSES OF UNEMPLOYMENT)

(1) बढ़ती जनसंख्या के कारण श्रम की पूर्ति में वृद्धि—बेरोजगारी में तीव्र गति से वृद्धि का मुख्य एवं महत्वपूर्ण कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है जिसके फलस्वरूप श्रम की पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है, जबकि रोजगार के अवसर उसी दर से नहीं बढ़ रहे हैं।

(2) दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली—ऐसे देशों में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण उनकी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। यहां शिक्षा सैद्धान्तिक प्रधान है, जबकि इसका व्यवसाय-प्रधान (Job-oriented) होना चाहिए।

(3) हस्तकला एवं लघु उद्योगों की अवनति—बेरोजगारी बढ़ने में हस्तकला एवं लघु उद्योगों की अवनति भी काफी योगदान देती है। इन उद्योगों की अवनति का प्रमुख कारण विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा है।

(4) त्रुटिपूर्ण नियोजन—विकासशील देशों में आर्थिक विकास हेतु नियोजन की नीति अपनायी जा रही है, लेकिन यह नियोजन पर्याप्त नहीं है।

(5) पूंजी-निर्माण की कमी—इन देशों में पूंजी-निर्माण की गति धीमी है जिससे उद्योगों का विकास भी धीमा है।

(6) तकनीकी एवं यंत्रीकरण—आधुनिक तकनीक के प्रयोग से श्रमिकों की आवश्यकता कम हो जाती है जिससे बेरोजगारी बढ़ती है।

(7) दोषपूर्ण दृष्टिकोण—शिक्षित व्यक्ति नौकरी करना पसंद करते हैं, जबकि वे स्वयं उत्पादन कार्य में नहीं लगना चाहते।

(8) मजदूरी व उत्पादकता में अन्तर—उत्पादकता की तुलना में मजदूरी बढ़ने से लागत बढ़ती है जिससे उत्पादन कम होता है और बेरोजगारी बढ़ती है।

बेरोजगारी दूर करने के उपाय (SUGGESTIONS TO SOLVE THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT)

(1) जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण—बेरोजगारी दूर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर उचित नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए। भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर 1.64 प्रतिशत वार्षिक है जो अधिक है।

(2) शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन—वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसे रोजगार-उन्मुख (Employment-oriented) बनाया जाना चाहिए जिसके लिए व्यावसायिक शिक्षा का विकास किया जा सकता है।

(3) कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास—बेरोजगारी दूर करने के लिए सुझाव दिया जाता है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कि कम पूंजी निवेश पर अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। इसके लिए ऐसे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए जो श्रमप्रधान हों।

(4) प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग—सरकार को प्राकृतिक साधनों के वितरण का अध्ययन करके उन क्षेत्रों का विकास करना चाहिए जहाँ अधिक रोजगार सृजन की सम्भावना हो।

(5) कृषि पर आधारित उद्योग-धन्धों का विकास—भारत में कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी पायी जाती है। अतः कृषि से जुड़े सहायक उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग आदि।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन—गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली आदि सुविधाओं का विकास करके रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए।

(7) श्रम का उचित उपयोग—देश में उपलब्ध श्रम शक्ति का उचित उपयोग किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि हो सके।

(8) जनशक्ति नियोजन—देश में जनशक्ति नियोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि विभिन्न क्षेत्रों में श्रम की मांग एवं पूर्ति का संतुलन बना रहे।

(9) निवेश में वृद्धि—देश में निवेश बढ़ाने के लिए बचत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे नए उद्योग स्थापित हों और रोजगार के अवसर बढ़ें।

(10) नई तकनीकों का विकास—नई तकनीकों का विकास एवं प्रसार किया जाना चाहिए जिससे उत्पादन क्षमता बढ़े और रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

भारत में बेरोजगारी नियन्त्रण की नीति (POLICY FOR CONTROLLING UNEMPLOYMENT IN INDIA)

भारत में बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास (STEPS TAKEN BY GOVERNMENT TO REDUCE UNEMPLOYMENT IN INDIA)

सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं—

(1) सामान्य रोजगार—सरकार उद्योगों में भारी निवेश करके रोजगार के अवसर बढ़ा रही है।

(2) विशेष रोजगार कार्यक्रम—शिक्षित बेरोजगारों के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई हैं।

(3) रोजगार सेवाएं—रोजगार कार्यालयों की स्थापना करके बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया गया है।

(4) कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास—छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।

(5) बेरोजगारी भत्ता—कुछ राज्यों में बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है।

(6) अन्य उपाय—सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि के माध्यम से रोजगार सृजन किया जा रहा है।

भारत में शिक्षित बेरोजगारी (EDUCATED UNEMPLOYMENT IN INDIA)

शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ उस बेरोजगारी से है जिसमें शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता।

इसके प्रमुख कारण हैं—

(1) शिक्षा का विस्तार—शिक्षा के प्रसार से शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ी है परन्तु रोजगार के अवसर उतने नहीं बढ़े।

(2) दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली—शिक्षा अधिक सैद्धान्तिक है, व्यावहारिक नहीं।

(3) मानसिकता में परिवर्तन—शिक्षित व्यक्ति केवल सफेदपोश नौकरियों की ओर आकर्षित होते हैं।

(4) प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी—व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव है।

(5) सूचना का अभाव—रोजगार सम्बन्धी सही जानकारी का अभाव।

शिक्षित बेरोजगारी कम करने के लिए सरकारी प्रयास

(1) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु सहायता

(2) परिवहन सुविधाओं का विकास

(3) स्वरोजगार कार्यक्रम

(4) इंजीनियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(5) ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(6) राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

(7) जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

(8) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)

शिक्षित बेरोजगारी कम करने के लिए सुझाव

(1) शिक्षा प्रणाली में सुधार

(2) प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार

(3) रोजगार सूचना केन्द्रों की स्थापना

(4) मानसिकता में परिवर्तन

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी : मौसमी एवं छिपी बेरोजगारी

(RURAL UNEMPLOYMENT IN INDIA : SEASONAL AND DISGUISED)

भारत की लगभग *69 प्रतिशत जनसंख्या* गाँवों में रहती है। यहाँ रोजगार के अवसर सीमित होते हैं जिससे ग्रामीण बेरोजगारी पायी जाती है।

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी दो प्रकार की पायी जाती है—
(1) मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)
(2) छिपी बेरोजगारी (Disguised Unemployment)

मौसमी बेरोजगारी कृषि कार्यों में समय विशेष पर ही रोजगार मिलने के कारण होती है।

छिपी बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य में लगे होते हैं, परन्तु उनके हटने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

ग्रामीण बेरोजगारी के कारण

(1) भूमि के प्रति प्रेम

(2) उत्तराधिकार नियम

(3) लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव

(4) संयुक्त परिवार प्रणाली

(5) कृषि पर अधिक निर्भरता

(6) ग्रामीण वातावरण के प्रति लगाव

ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के उपाय

(1) लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास

(2) ग्रामीण सामाजिक वातावरण में परिवर्तन

(3) प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास

ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के सरकारी प्रयास

(GOVERNMENT EFFORTS TO REMOVE RURAL UNEMPLOYMENT)

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम—मनरेगा
(Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act—MNREGA)

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'मनरेगा' भारत सरकार की महत्वपूर्ण 'फ्लैगशिप' योजना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार के ऐसे वयस्क सदस्य को, जो शारीरिक श्रम करना चाहता है, वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। यह योजना महिलाओं को 1/3 रोजगार प्रदान करती है। योजना का प्रमुख उद्देश्य मजदूरी रोजगार बढ़ाना है। यह एक मांग-आधारित योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, भूमि विकास, जल संरक्षण, सूखा-रोधी उपाय, वृक्षारोपण आदि कार्य कराए जाते हैं।
इस योजना के अंतर्गत रोजगार की मांग करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है।

मनरेगा प्रथम चरण में 2 फरवरी, 2006 से 200 जिलों में लागू किया गया। बाद में इसे 130 और जिलों तक विस्तारित किया गया तथा 1 अप्रैल, 2008 से यह देश के सभी जिलों में लागू हो गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नया नाम ***विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G]*** (Viksit Bharat - Guarantee For Rozgar and Ajeevika Mission) कर दिया गया है।

इस नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को हर साल **100 की जगह 125 दिनों** का गारंटीड रोजगार मिलेगा।

मनरेगा (MGNREGA) में मुख्य बदलाव:

- **नया नाम:** विकसित भारत - जी राम जी (VB-G RAM G)
- **काम के दिन:** 100 से बढ़ाकर 125 दिन।
- **भुगतान:** अब साप्ताहिक (weekly) आधार पर भुगतान होगा।
- **लक्ष्य:** 2047 तक विकसित भारत के विजन के साथ मिलकर काम करना।
- **मुख्य उद्देश्य:** ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रोजगार की गारंटी को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना।

यह बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका और बेहतर अवसंरचना के लिए किया गया है।

2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

यह योजना 1 अप्रैल, 1999 से प्रारम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना तथा ग्रामीण गरीबों को स्व-सहायता समूहों (Self Help Groups) के माध्यम से ऋण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

अब इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार एवं कुशल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

यह योजना 25 दिसम्बर, 2000 को प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत लाखों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

यह मिशन 2011 में प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को संगठित करके उन्हें स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

5. स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम

इस कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी, 2016 को की गई। इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

6. स्टैंड-अप इंडिया कार्यक्रम

यह योजना अप्रैल 2016 में प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना है।

7. विजन-2020 फॉर इंडिया

यह एक दीर्घकालीन योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।